<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हरित इस्पात के विकास के लिए नीति, वित्तीयन और प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल का आग्रह

मुंबई, 19 सितंबर, 2025

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास द्वारा आज इंडिया स्टीलेक्स 2025 में "वित्तीय साधन: वैश्विक स्तर पर मेक-इन-इंडिया इस्पात को बढ़ावा देना" विषय पर आयोजित सत्र और बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र, मुंबई में "लाभदायक स्थिरता - हरित इस्पात: भविष्य का एक पारिस्थितिकी तंत्र" विषय पर आयोजित 37वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई ।

इस अवसर पर नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के अगुओं और वित्तपोषकों को संबोधित करते हुए, श्री दास ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तेज़ और सुशासित डीकार्बोनाइज़ेशन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि , "ग्रीन स्टील एक समाधान से नहीं आएगा; ये चार कारकों पर निर्भर करते हैं - नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, स्क्रैप से चलने वाली इलेक्ट्रिक-आर्क भट्टियाँ, और एक स्पष्ट वर्गीकरण द्वारा समर्थित कार्बन कैप्चर।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ग्रीन वर्गीकरण वैधानिक स्पष्टता, पारदर्शी मानक और निवेशक को विश्वास प्रदान करने की कुंजी है—जोकि सीसीयूएस और दक्षता उन्नयन जैसी तकनीकों का मार्गदर्शन करता है।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा की गति पर प्रकाश डालते हुए, श्री दास ने बताया कि बिजली के उत्पादन में लगभग 50% गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी (अगस्त 2025 तक) के साथ लगभग 242 गीगावाट की नवीकरणीय क्षमता विकसित की गई है और इस वित्तीय वर्ष के केवल पाँच महीनों के दौरान लगभग 22 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महाराष्ट्र के नेतृत्व और कृषि को सौर ऊर्जा से जोड़ने तथा नवीकरणीय ऊर्जा आधार को और मज़बूत करने के लिए पीएम-कुसुम जैसी पहलों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि मांग को बनाए रखने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) आवश्यक हैं, और भारत की लगभग 80% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की जाती है, जोकि बड़े पैमाने पर पूँजी जुटाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इरेडा के अभिशासन-आधारित विकास और जोखिम-मुक्ति के अधिदेश को दोहराते हुए, श्री दास ने कहा कि कंपनी ने 38 वर्षों के दौरान ₹1.63 लाख करोड़ से अधिक का वित्तपोषण किया है, जिसमें केवल ₹135 करोड़ का संचयी राइट-ऑफ शामिल है, जोकि मज़बूत अभिशासन और वसूली मानकों को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि , "हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आवश्यक लेकिन उभरते क्षेत्रों—हरित हाइड्रोजन से लेकर भंडारण और सौर विनिर्माण तक—को जोखिम-मुक्त करें ताकि भारत ना केवल इन तकनीकों को अपना सके, बल्कि उनका विनिर्माण और निर्यात भी कर सके।" इरेडा के सीएमडी द्वारा हरित इस्पात के विस्तार के लिए रियायती और मिश्रित वित्तपोषण , हरित बॉण्ड, ईएसजी-लिंक्ड ऋण और हरित सार्वजनिक खरीद को प्रमुख उपकरणों के रूप में रेखांकित किया गया ।

इरेडा के सीएमडी ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि, "मेक-इन-इंडिया इस्पात को ना केवल मात्रा के लिए होना चाहिए, बल्कि गुणवत्ता और टिकाऊ के लिए भी वैश्विक स्तर पर चमकना चाहिए। "